आकाशवाणी
क्षेत्रीय समाचार
देहरादून उत्तराखण्ड)
सोमवार 28.07.2025

मुख्य समाचार :–

- प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के दूसरे चरण का मतदान शांतिपूर्ण सम्पन्न। अंतिम समाचार मिलने तक 58 प्रतिशत से अधिक मतदान की खबर।
- 14 हजार 751 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला मतपेटियों में बंद। 31 जुलाई को होगी मतगणना।
- मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने धर्मांतरण के कानून को और सख्त करने के निर्देश दिए। ऑपरेशन कालनेमि की निगरानी के लिए पुलिस मुख्यालय स्तर पर गठित होगी एसआईटी।
- दून विश्वविद्यालय और राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर।

मतदान

प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के दूसरे चरण में आज 40 विकासखंडों में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मतदान शांतिपूर्ण ढंग से सम्पन्न हुआ। इसके साथ ही विभिन्न पदों के लिए 14 हजार 751 प्रत्याशियों का भाग्य भी मतपेटियों में बंद हो गया। अंतिम समाचार मिलने तक प्रदेश में 58 प्रतिशत से अधिक मतदान की खबर है। वहीं, मतदान के लिए प्रदेश में 4 हजार 709 मतदेय स्थलों पर सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए थे। आज सुबह से ही बड़ी संख्या में मतदाता, राज्य के विभिन्न मतदान केंद्रों में वोट डालने पहुंचे। बुजुर्ग मतदाताओं के साथ ही दिव्यांग मतदाताओं ने मतदान में बढ़–चढ़कर भाग लिया। इस दौरान लोगों में, विशेषकर युवा मतदाताओं में खासा उत्साह दिखाई दिया। मतदाताओं का कहना था कि वो ऐसे उम्मीदवार चाहते हैं, जो गांव के समुचित विकास के साथ ही सरकार की योजनाओं को धरातल पर उतार सके।

मतदान पौड़ी

पौड़ी गढ़वाल में सात विकासखण्डों– पौड़ी, कोट, कल्जीखाल, जयहरीखाल, द्वारीखाल, यमकेश्वर और दुगड्डा विकासखंडों के 548 मतदेय स्थलों पर मतदान शांतिपूर्ण सम्पन्न हुआ। गढ़वाल लोकसभा सांसद अनिल बलूनी ने राजकीय प्राथमिक विद्यालय, खोला में पोलिंग बूथ पर वोट डाला। उन्होंने कहा कि पहाड़ को बचाने के लिए आवश्यक है कि हम तीज त्योहारों में, चुनाव के अवसर पर और पारिवारिक उत्सवों में गांव जरूर आएं।

मतदान के लिए पौड़ी से अपने गांव देवलकोट ब्लॉक आई मतदाता हेमलता भट्ट ने कहा गांव के विकास की पहली इकाई ग्राम पंचायत हैं। इसीलिए वे अपने गांव के प्रतिनिधियों के चयन के लिए आईं।
राज्य के अन्य जिलों में भी मतदान शांतिपूर्ण सम्पन्न हुआ। गौरतलब है कि पंचायत चुनाव के पहले चरण का मतदान 24 जुलाई को हुआ था। दोनों चरणों की मतगणना 31 जुलाई को होगी।

मुख्यमंत्री निर्दे

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश के प्रमुख धार्मिक स्थलों– मनसा देवी, चंडी देवी मंदिर, पूर्णागिरि धाम, कैंची धाम, जागेश्वर मंदिर और नीलकंठ महादेव मंदिर सहित अन्य प्रसिद्ध मंदिरों में श्रद्धालुओं की संख्या को ध्यान में रखते हुए समुचित व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। आज सचिवालय में उच्च स्तरीय बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि इन मंदिरों में भीड़ प्रबंधन, श्रद्धालु पंजीकरण, पैदल मार्गों और सीढ़ियों का चौड़ीकरण, अतिक्रमण हटाने और अन्य सभी मूलभूत सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए, ताकि श्रद्धालुओं को सुगम व सुरक्षित दर्शन हो सकें। उन्होंने गढ़वाल और कुमाऊं मडंल के आयुक्तों की अध्यक्षता में एक समिति का गठन करने और समिति में संबंधित जिलों के जिलाधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, विकास प्राधिकरणों के उपाध्यक्ष और कार्यदायी संस्थाओं के प्रतिनिधियों को सदस्य के रूप में शामिल करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने विशेष रूप से मनसा देवी मंदिर परिसर और अन्य प्रमुख मंदिर परिसरों के सुनियोजित विकास, धारणा क्षमता में वृद्धि और व्यवस्थित दुकान प्रबंधन पर बल देते हुए श्रद्धालुओं के लिए दर्शन की व्यवस्था को सुदृढ़, सुव्यवस्थित और सुगम बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि श्रद्धालुओं का पंजीकरण अनिवार्य रूप से किया जाए। साथ ही दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं की संख्या नियंत्रित करते हुए चरणबद्ध व्यवस्था सुनिश्चित की जाए, ताकि भीड़ नियंत्रण में रहे और श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो।

धर्मान्तरण कानून

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश में हाल की घटनाओं को देखते हुए धर्मांतरण कानून को और सख्त बनाने के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। सचिवालय में आज उच्च अधिकारियों के साथ बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड सीमांत प्रदेश होने के साथ ही सनातन की पुण्य भूमि भी है। इसलिए यहां डेमोग्राफी में बदलाव की किसी भी कोशिश को सख्ती से रोका जाए। उन्होंने पुलिस को इस तरह की संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखने को कहा। मुख्यमंत्री ने धर्मांतरण कराने वाले तत्वों के जाल में फंसे लोगों को उचित परामर्श और मार्गदर्शन प्रदान करने पर बल दिया। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन कालनेमि भी ऐसे तत्वों

पर लगाम लगाने में सफल रहा है। उन्होंने कहा कि इस मुहिम को आगे भी चलाए जाने की जरूरत है, इसलिए पुलिस मुख्यालय के स्तर पर, इसकी निगरानी के लिए एसआईटी का गठन किया जाए।

समझौता ज्ञापन

राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह की पहल पर राजभवन में आज दून विश्वविद्यालय और राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम– एनआरडीसी के बीच एक महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। यह राज्य में अपनी तरह की पहली साझेदारी है, जिसमें एनआरडीसी ने किसी राज्य विश्वविद्यालय से औपचारिक रूप से समझौता किया है। एनआरडीसी, केंद्र सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय का एक उपक्रम है, जिसका उद्देश्य अनुसंधान और नवाचार को प्रोत्साहित करना तथा बौद्धिक सम्पदा का व्यावसायीकरण करना है। इस अवसर पर राज्यपाल ने कहा कि यह पहल प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के 'विकसित भारत–2047 के विजन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा कि यह समझौता दून विश्वविद्यालय को एक ऐसा मंच प्रदान करेगा, जहां अनुसंधान कार्य अकादमिक दायरे से निकलकर उद्योगों, स्टार्टअप्स और राष्ट्रीय प्राथमिकताओं से जुड़ सकेगा। इससे विश्वविद्यालय आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ेगा और बाहरी वित्तीय संसाधनों पर निर्भरता कम होगी। इस अवसर पर एनआरडीसी के अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक कमोडोर अमित रस्तोगी ने राज्यपाल को आश्वस्त किया कि एनआरडीसी, दून विश्वविद्यालय को हरसंभव सहयोग प्रदान करेगा।

मसूरी–देहरादून रोपवे

मसूरी और देहरादून के बीच यातायात जाम की समस्या से लोगों को जल्द निजात मिलेगी। पर्यटन विभाग ने मसूरी–देहरादून रोपवे योजना पर काम करना शुरू कर दिया है। पर्यटन सचिव धीराज गर्ब्याल ने बताया कि रोपवे के बनने से न केवल पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि ट्रैफिक की स्थिति में भी सुधार होगा।

समान नागरिक संहिता

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता– यूसीसी लागू कर, राज्य सरकार ने बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को सच्ची श्रद्धांजलि देने का काम किया है। उन्होंने कहा यू.सी.सी लागू होने के बाद अब राज्य में सभी नागरिकों के अधिकार समान हो गए हैं। यू.सी.सी ने समाज में भेदभाव खत्म करने का काम किया है। यूसीसी लागू करने पर आज देहरादून में आयोजित सम्मान समारोह में मुख्यमंत्री ने कहा कि समान नागरिक संहिता में महिलाओं के अधिकारों को सुरक्षित किया गया है। उन्होंने कहा हमारी विचारधारा सामाजिक समरसता, सांस्कृतिक चेतना और राष्ट्रीय एकता जैसे मूल्यों पर आधारित रही है।